सम्पादक के नाम

रेफल कहीं मोदी को न ले डूबे ?

लड़ाकू विमान रेफल के सौदे ने अब बड़ा खतरनाक मोड़ ले लिया है। फ्रांस के पूर्व राष्ट्रपति फ्रांस्वा ओलांद ने इसी विमान से मोदी सरकार पर बम बरसा दिए हैं। वह विमान बनने के बाद भारत आएगा या नहीं, कुछ पता नहीं लेकिन यह भी पता नहीं कि मोदी सरकार अब अपनी जान कैसे बचाएगी ? जैसे बोफर्स राजीव गांधी को ले डूबा, कहीं वैसे ही रेफल मोदी को न ले डूबे।

ओलांद ने एक फ्रांसीसी पत्रकार को रेफल-सौदे के बारे में जो इंटरव्यू दिया है, उसमें उन्होंने साफ-साफ कहा है कि अनिल अंबानी की कंपनी को इस सौदे में शामिल करने का प्रस्ताव भारत सरकार ने दिया था। वे भारत सरकार के प्रस्ताव को रद्द कैसे करते ? ओलांद ने यह बयान क्यों दिया? इसलिए दिया कि फ्रांस के अखबारों में उन पर यह आरोप लग रहा था कि वे अपनी प्रेमिका जूली गाए को खुश करना चाह रहे थे। जूली उनके साथ 26 जनवरी 2016 को भारत आई थी। वह एक बहुत मंहगी फिल्म बना रही थी। अंबानी ने उसे पटाया। 85 करोड़ रु. की फिल्म का एक चौथाई खर्च अंबानी ने उठाने का वादा किया याने लगभग 20-21 करोड़ रु. की रिश्वत दे दी। इस आरोप से बचने के लिए ही ओलांद ने सफाई दी और कहा कि उन्हें इस फिल्म के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। ओलांद ने खुद को बचा लिया लेकिन मोदी को फंसा दिया।

सरकार की सिट्टी-पिट्टी गुम है। रक्षा मंत्रालय आंय-बांय-शांय कर रहा है। रक्षा मंत्री निर्मला सेतुरामन के सिर के ऊपर से पानी बह रहा है। उन्हें क्या पता कि मोदी, अंबानी और ओलांद के बीच क्या खिचड़ी पक रही थी? मोदी ने ओलांद को गणतंत्र दिवस (2016) पर मुख्य अतिथि आखिर क्यों बनाया ? अनिल अंबानी जैसे विफल उद्योगपति को लड़ाकू जहाज बनाने की अनुमति कैसे दे दी ? अंबानी को 2015 में मोदी अपने साथ पेरिस क्यों ले गए थे ? जहाज बनानेवाली सरकारी कंपनी हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लि. की जगह एक गैर-सरकारी कंपनी, जो कल पैदा हुई और जिसको विमान-निर्माण का कोई अनुभव नहीं, उसे यह सौदा कैसे मिल गया ? और सबसे बड़ा सवाल यह है कि 500 करोड़ के जहाज की कीमत 1600 करोड़ रु. कैसे हो गई ?

60 हजार करोड़ रु. के इस सौदे में फ्रांसीसी कंपनी दुस्साल्ट को यदि 15 हजार करोड़ भी दे दिए गए तो प्रश्न यह है कि शेष 45 हजार करोड़ रु. का क्या होगा ? वे किसकी जेब में जाएंगे ? अनिल अंबानी को 5-10 हजार करोड़ से ज्यादा मिलना तो असंभव है। तो क्या बोफर्स की तरह वे फिर लौटकर दबे-छुपे भारत ही आएंगे ? इस प्रश्न को जोरों से उठानेवाले हमारे 'पप्पू' का चप्पू अब 'गप्पूजी' की खाल उधेड़कर रख देगा। गप्पूजी के पास अभी भी मौका है। रेफल विमान अभी बनने शुरु नहीं हुए हैं, बोफर्स की तरह। उसे रद्द करने में ही समझदारी है। डर यही है कि कहीं सौदा रह न जाए और सरकार ढह न जाए।

-वेद प्रताप वैदिक

मोदी जी अगर पुरानी पेंशन नीति बहाल न करें तो क्या कर लेंगे ?

******जिस पार्टी ने नई पेंशन नीति लागू की

******सरकारी विभागों शिक्षा स्वास्थ्य सब जगह संविदा ठेका मजदूरी लागू की।

*******सरकारी उद्यमों को कंपनी मालिकान को बेचने के लिए मंत्रालय बनाया

******क्या वो अब पुन: पुरानी पेंशन नीति बहाल करेगी?

पिछले अनुभव के आधार पर कहा जा सकता है कि भाजपा सरकार मजदूर किसान कर्मचारी के लिए हितकारी नहीं रही । अब तो वे देश के छोटे व्यापारी के खिलाफ अमेजान; फ्लिपकार्ट; वालमार्ट को बढ़ावा दे रहे हैं।

*** इसका क्या कारण है?

*** इसका कारण संभवतया राजनीतिक दलों की विदेशी फंडिंग है?

***दूसरा कारण नेताओं और कंपनी मालिकान की विदेशी कंपनियो में भागीदारी (शेयर-लाभांश) लगता है ।

*****राजनीतिक दलों का अपने-अपने संगठन पर आत्मनियंत्रण नहीं है। कार्यकर्ता का अपनी पार्टी और नेतृत्व पर नियंत्रण नहीं है।

*****जनता का राजनीतिक दलों की नीतियों और वादों पर कोई नियन्त्रण नहीं है । अगर राजनीतिक दल अपनी जनता और देश के लिए बने हैं तो कार्यकर्ता और नागरिक सदस्य का अपने दल उसके नीति सिद्धांत कार्यक्रम और नेतृत्व पर संवैधानिक नियंत्रण होना चाहिए ?

****इतिहास हमें बताता है कि :

मीर जाफर को प्लासी के युद्ध में (1757) ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना के साथ मिलकर नवाब सिराजुद्दौला की हत्या के लिए तत्कालीन "जगत सेठ ने" 20 लाख रुपए नकद दिया और क्लाइव की ओर से बंगाल का शासन सौंपने का वादा हुआ । क्लाइव के साथ मीरजाफर की मीटिंग "जगत सेठ ने " कराई थी।

***जगत सेठ ने ऐसा क्यों किया?

इतिहासकार कहते हैं कि जगत सेठ ने ऐसा किया क्योंकि कंपनी के साथ उनकी व्यापारिक भागीदारी थी! जगत सेठ ने ब्रिटिश कंपनी को व्यापार के लिए भारी कर्ज दे रखा था । यदि कंपनी भारत से हारकर चली जाती तो जगत सेठ दीवालिया हो जाते!

****अत: इतिहास का सबक क्या है?

जिन देशभक्त (?) कंपनी मालिकान, दलों और नेताओं की विदेशी साझेदारी (एफडीआई) हो विदेशी कंपनियो के लाभांश में हिस्सेदारी हो राष्ट्रीय हित उनकी प्राथमिकता नहीं रह सकता है? वे मीर जाफर और जगत सेठ की भूमिका निभाने लगते हैं।

****इसीलिये उन्हें अपनी प्रजा को जाति-धर्म के झगड़े में उलझाना पड़ता है?

**** पता करिए कि भारत ; पाकिस्तान को क्या-क्या बेच रहा है? पाकिस्तान के सजायाफ्ता नवाज शरीफ साहब से बिन बुलाए मिलने के लिए किसके कहने पर प्रधान सेवक जी सीधे एकाएक आसमान से कूद पड़े थे?

-राम कृष्ण

खबर (दार) झरोखा

विकास नारायण राय

कहीं संघ के एजेंडे के शिकार तो नहीं हो रहे राहुल गांधी

यदि मौका मिला तो राहुल गांधी अपने पिता से बेहतर प्रधानमंत्री सिद्ध होंगे। एक तो उनके सलाहकार अनुभवी हैं और दूसरे उनका संघ विरोध सतही नहीं है।

मेरा अरसे से विश्वास रहा है कि यदि मौका मिला तो राहुल गांधी अपने पिता से बेहतर प्रधानमंत्री सिद्ध होंगे। एक तो उनके सलाहकार अनुभवी हैं और दूसरे उनका संघ विरोध सतही नहीं है। उन्हें दस वर्ष के यूपीए कार्यकाल में परदे के पीछे से गलतियां देखने और शायद करने का अनुभव भी है। राजीव गांधी इन अवसरों से वंचित रहे थे।

आश्चर्यजनक रूप से, इस बार राहुल गांधी का प्रधानमंत्री बनना उनके नेहरू परिवार का वारिस होने से नहीं तय होने जा रहा। यह सुविधा 2004 और 2009 में उनके पास रही होगी। इस बार के चुनाव में आरएसएस केन्द्रित ध्रुवीकरण की खासी भूमिका रहेगी। लिबरल अमेरिका को ट्रम्प विरोध में आयोजित होते देखिये और इसमें मोदी विरोध की भारतीय छवि को पहचानिये।

भारत और अमेरिका, दुनिया के दो सबसे बड़े लोकतंत्र, इस समय दो फासिस्ट शासकों के हाथों संचालित हो रहे हैं। भारत में शायद ही संदेह हो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना पूरा कार्यकाल, सवर्ण प्रभुत्ववादी संगठन आरएसएस का मानस पुत्र बने रहना है। इसी तरह अमेरिका में भी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प को व्हाइट प्रभुत्ववादी विचारधारा कू क्लक्स क्लान का सहज ही मानस पुत्र मानने वालों की कमी नहीं।

तब भी, संकुचित कू क्लक्स क्लान के 1980 के दशक से लक्षित तीसरे संस्करण को आज के अमेरिका में औपचारिक रूप से कोई धार्मिक, सामाजिक या राजनीतिक संगठन मान्यता देता नहीं दिखता। एक राष्ट्र के रूप में अमेरिका की ऐतिहासिक बहुलतावादी निर्मिति की ही ताकत है यह! गाँधी और नेहरु के आधुनिक भारत में यह मंजिल अभी दूर है।

हाल में दिल्ली में तीन दिन के बहुप्रचारित आरएसएस आयोजन में संघ प्रमुख मोहन भागवत ने किसी नयी हिन्दू एकता की बात नहीं की है। संघ पोषित हिन्दू एकता, वेद, उपनिषद, पुराण और स्मृति की जातिवादी और भाग्यवादी एकता से इतर कुछ हो भी नहीं सकती।

अमेरिका में इतिहास के प्रोफेसर थॉमस पेग्राम ने अमेरिकी पहचान के स्वयंभू ठेकेदार कू क्लक्स क्लान के अमेरिकी समाज में घुसपैठ और तिरोहित होने की शोध गाथा को 'वन हंड्रेड परसेंट अमेरिकन' का सटीक शीर्षक दिया है। उनकी यह किताब 2011 में बराक ओबामा के शासनकाल में आयी थी। आरएसएस आज भारत में सत्ता की नैया की पतवार बना हुआ है; पेग्राम की तर्ज पर कहें तो दिल्ली बैठक में भागवत एक 'विशुद्ध भारतीय' मानक गड़ने की स्वयंभू ठेकेदारी कर रहे थे।

1920 के दशक में जब भारत में हिन्दुत्ववादी संघ के सफर की शुरुआत हो रही थी, अमेरिका में क्लान अपने दूसरे ऐतिहासिक संस्करण के उफान को जीकर सीतनिद्रा में पहुंच रहा था। उसकी ऊर्जा मुख्यत: प्रथम विश्वयुद्ध (1914-1919) के बाद यूरोप से अमेरिका आने वाले रोमन कैथोलिक और यहूदी आव्रजक का विरोध करने में खर्च हुई।

अंतत: कठोर प्रशासनिक कदमों ने उनकी कमर तोड़ दी। जबकि भारत में संघ को राजनीति में तिलक और हिन्दू महासभा की बनायी जमीन और समाज में हिन्दू-मुस्लिम खींचतान की हवा रास आती गयी थी। 1948 में महात्मा गांधी की हत्या के बाद के राष्ट्रव्यापी आक्रोश ने ही उसके मार्च को पस्त किया।

उस दौर में संघ, मराठी चितपावन ब्राह्मण श्रेष्ठता और क्लान, नार्डिक प्रोटेस्टेंट व्हाइट श्रेष्ठता की अवधारणा को केंद्र में रखने वाले संगठन रहे। कालांतर में दोनों ने संशोधित रणनीतियां चुनीं। आज क्लान और संघ विचारधाराएं समान रूप से मुस्लिम विरोध राजनीति की राष्ट्रवादी धुरी पर सत्ता संतुलन बैठा रही हैं। संयोग से आज दोनों के निशाने पर नफरत के रास्ते पर ब ?ते रहने के लिये एक जैसे उत्प्रेरक राष्ट्रीय हौव्वे भी उपलब्ध हैं- मुस्लिम आतंकी और मुस्लिम आव्रजक।

अमेरिका में, गृहयुद्ध (1861-65) में मिली पराजय और परिणामस्वरूप दास प्रथा की समाप्ति ने दक्खिन संघ के पराजित राज्यों में क्लान का पहला संस्करण पैदा किया था। स्वाभाविक रूप से उनके हिंसक निशाने पर विजेताओं की 'रिकंस्ट्रक्शन' नीतियां और आजाद हुये अफ्रीकी मूल के अमेरिकी रहे। 1870 के दशक में क्लान विरोधी कानूनों के व्यापक इस्तेमाल से उसकी हिंसा को कुचला जा सका।

1876 के राष्ट्रपति पद पर चुनाव के विवादित नतीजों को लेकर हुए दोनों पक्षों के राजनीतिक समझौते से इन राज्यों से फेडरल फौजें हटा ली गयीं और इनमें कुछ हद तक व्हाइट रेडीमर्स का बोलबाला स्वीकार्य हो गया। इससे भी लोगों में क्लान की अतिवादी अपील कमजोर होती गयी।

आधुनिक दौर में क्लान की तरह संघ भी एक बेहद पिछड़ी विचारधारा सिद्ध है। उसे भी अपने अंध राष्ट्रवाद और मानवाधिकार विरोध के बरक्स तथाकथित सांस्कृतिक मूल्यों और सनातनी गौरव का नैतिक चैंपियन बने रहना है। क्लान का इतिहास बताता है कि जहरीली विचारधारा की उम्र लम्बी हो सकती है, लेकिन उनके सैन्यवादी संगठन कानून ध्वस्त किये जा सकते हैं।

इस परिप्रेक्ष्य में राहुल गांधी को राजनीति के जनेऊ अवतार में मानसरोवर यात्रा का साक्षी बनते देखना उनके पिता स्वर्गीय राजीव गांधी की याद दिला गया। राजीव के नेतृत्व में कांग्रेस भाजपा के टर्फ पर उतरती गयी थी और पिटती भी। खालिस्तानी आतंक की पृष्ठभूमि में इंदिरा गांधी की हत्या से कांग्रेस को लहलहाती वोट फसल हासिल हुई थी।

इसी ललक में, उनके कार्यकाल में, शाहबानो, हाशिमपुरा-मलियाना, भागलपुर, राम मंदिर शिलान्यास जैसे साम्प्रदायिक पड़ाव बनते गये। यहां तक कि, बोफोर्स चक्रव्यूह से निकलने के लिए वे नवम्बर 1989 में अयोध्या के विवादास्पद स्थल पर पूजा के बाद राम राज्य लाने के वादे के साथ चुनाव प्रचार में निकले और भाजपा राजनीति को और बल दे गये।

राहुल के लिये भी ज्यादा वक्त नहीं है- संघ के टर्फ पर खेलोगे तो फिसल जाओगे!

एक ढूंढो दस मोदी घोटाले मिलेंगे- यकीनन

मजदूर मोर्चा, विशेष रिपोर्ट

फ्रांस के पूर्व राष्ट्रपति फांसवा ओलांद ने फ्रांस की एक वेबसाइट मिडियापार्ट से लेख में दावे के साथ कहा है कि भारत सरकार ने रिलायंस डिफेंस को राफेल सौदा दिलवाने का दबाव डाला। इस रहस्योद्घाटन से सरकार के उस दावे की पोल खुल गई जिसमें कहा गया था की राफेल सौदा सरकार और सरकार के मध्य था (जी टू जी डील), बहरहाल अभी सिर्फ एक मुद्दे पर जनता का ध्यान आकर्षित किया गया है और सौदों को भी देखें, ध्यान से देखें अनिल अंबानी के आगे पूरी सरकार नतमस्तक है और एक नाकारा व्यक्ति को सौदे पर सौदे दिलाकर मोदी ने देश को लाखों करोड़ का नुकसान किया है।

रिलायंस डिफेंस को अब रिलायंस नेवल के नाम से जाना जाता है 2014 से पहले इस कंपनी के बारे में कोई जानकारी नहीं थी मोदी जी के सत्ता संभालते ही मोदी जी की योजना मेक इन इंडिया,और स्टार्ट अप इंडिया का जादुई फायदा रिलायंस नेवल को हुआ, अब रिलायंस डिफेंस (नेवल) को इजराइल,अमेरिका,फ्रांस,रूस,एमिरेट्स,जर्मनी से अचानक लाखों करोड़ के सौदे मिलने लगे, ये सब हुआ प्रधानमंत्री मोदी जी की मध्यस्थता से,इस संदर्भ में कुछ तथ्यों पर नजर डालते हैं।

1. सन 2015 से 2016 के बीच 35 डिफेंस से संबंधित लाइसेंस रिलायंस डिफेंस को मिलते हैं जिसमें 12 लाइसेंस 3 दिसंबर 2015 को एवं 16 लाइसेंस एक साथ 5 मई 2016 को दे दिए जाते हैं जिसमें मिसाइल बनाने के लाइसेंस भी सम्मिलित है

2. साथ ही नागपुर में 10 सप्ताह से भी कम समय में 289 एकड़ जमीन हेलीकॉप्टर बनाने के लिए दे दी जाती है आश्चर्य चकित करने वाला तथ्य देखिए रिलायंस 16 जून 2015 में महाराष्ट्र सरकार के समक्ष जमीन के लिए आवेदन करती है और 26 अगस्त 2015 को देवेंद्र फड़नवीस एक कार्यक्रम में जमीन से सम्बंधित कागजात दे देते हैं ये भारत के इतिहास में पहली बार था जब इतने कम वक्त में इतनी बड़ी जमीन का आवंटन निजी कंपनी को कर दिया गया।

रिलायंस डिफेंस जो अब रिलायंस नेवल है के साथ विभिन्न देशों की बड़ी हथियार निर्माता कंपनी और मोदी जी की विदेश यात्रा की टाइमिंग देखिए, सत्ता और औद्योगिक घरानों का घृणित गठबंधन नजर आएगा।

3. 24 दिसंबर ,2015 को रूस की कंपनी अलमज़ अन्ते ने रिलायंस डिफेन्स के साथ लगभग 42 हज़ार करोड़ का समझोता किया, इससे पहले दिसंबर सन 2015 के प्रथम सप्ताह में भारत सरकार ने रूस के साथ चार एस-400 एयर डिफेन्स सिस्टम खरीदने का 32000 हज़ार करोड़ का सौदा किया, गौर करें मोदी जी 23 और 24 दिसंबर 15 को रूस की आधिकारिक यात्रा पर थे।

4. 30 मार्च 2016 को इजराइल की कंपनी राफेल के साथ रिलायंस डिफेन्स (अनिल अम्बानी) की 65000 करोड़ की डील फाइनल हुई, और इससे पहले मार्च 3, 2016 को भारत सरकार ने दो अवाक्स (वार्निंग सिस्टम) खरीद का सौदा इज़राइल सरकार के साथ किया और इसके तुरंत बाद इजराइल की कौन्सिल जनरल येल हशवित ने कहा की मोदी जी शीघ्र ही इज़राइल की यात्रा करेंगे।

5. रिलायंस डिफेंस ने 21 जून 2017 को फ्रांस की कंपनी थेल्स के साथ राडार,और एयरबोर्न सिस्टम बनाने के लिए जॉइंट वेंचर बनाने का समझौता किया,इससे पहले सिंतबर 2016 में भारत फ्रांस के साथ 36 राफेल जेट विमान का समझौता 59000 करोड़ रुपये में कर चुका था यहां ध्यान देने वाली बात ये है कि थेल्स, दसॉल्ट फाल्कन जो कि भारत को राफेल उपलब्ध करवाएगा,उसे तकनीकी सहायता उपलब्ध करवाता है।

6.रिलायंस नेवल ने 3 अक्टूबर 2016 को फ्रांस की कंपनी दस्सोल्ट एविएशन के साथ रक्षा क्षेत्र में एक समझौता किया जिसके तहत दोनों कंपनी मिलकर भारत में राफेल के लिए कंपोनेंट बनाएंगे। इससे ठीक 10 दिन पहले भारत और फ्रांस 36 राफेल फाइटर जेट का सौदा 526 करोड़ के पूर्व भाव के स्थान पर 1570 करोड़ रु प्रति विमान कर चुके थे। कहने का सीधा अर्थ ये की फ्रांस ने राफेल डील के बदले में अनिल अंबानी की कंपनी के साथ राफेल के पुर्जे बनाने का समझौता किया।

7. दक्षिण कोरिया की ख़्ल्ल ह्श्वड्ड 1 के साथ रिलायंस नेवल ने 17 अप्रैल 2017 को सामरिक संबद्धता का समझौता किया ,जिसके तहत रिलायंस नेवल को मिलिट्री हार्डवेयर बनाने में साउथ कोरिया की फर्म सहायता करेगी, इससे पहले 2015 में सिओल में मोदी जी दक्षिण कोरिया के साथ रक्षा और सुरक्षा के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर सहमत हो चुकेथे।

8. रिलायंस नेवल ने फ्रांस की देहर ऐरोस्पेस के साथ 22 जून 2017 को समझौता किया,इससे पहले भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जून 2017 के पहले सप्ताह में फ्रांस की यात्रा पर थे ये उनकी तीसरी फ्रांस यात्रा थीं।

9. 6 जून 2015 को अनिल अम्बानी की कंपनी रिलायंस पावर को बांग्लादेश में 3 हज़ार मेगावाट का गैस बेस्ड पॉवर प्लांट एवं एल एन जी टर्मिनल लगाने का समझोता हुआ, उस वक्त 6 से 7 जून प्रधानमन्त्री जी बांग्लादेश की यात्रा पर थे। प्रश्न पुन: अनिल अंबानी भारत में गैस बेस्ड पॉवर प्लांट नहीं लगा पाए, फिर बांग्लादेश सरकार ने उन्हें किस आधार पर चुना ?

10. एक तथ्य पर गौर करें की एक ऐसी कंपनी जो की एक वर्ष में ही बनी है(रिलायंस डिफेन्स) उसे रूस,इजराइल ,फ्रांस से लगभग 1 लाख करोड़ के डील किस बिनाह पर मिले, साथ ही ये संयोग कैसे हुआ की पहले भारत सरकार ने खरीद के समझौते करोड़ के आर्डर उन्हें दिए,फिर अनिल अम्बानी की कंपनी के साथ डील हुई, ये भी कैसे हुआ की 35 बड़े लाइसेंस एक ही झटके में दे दिए गए ?

शेष पेज सात पर